

11. Eradication of hunger depends on the adequacy of policy intervention to curb the menace of hunger and starvation. In this context, discuss the concerns raised by recent reports on the hunger situation in India. (250 words) 15

भूख का उन्मूलन वस्तुतः भूख और भुखमरी के संकट को रोकने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों की पर्याप्तता पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में, भारत में भूख की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट्स द्वारा उजागर की गई चिंताओं पर चर्चा कीजिए।

दृष्टिकोण:

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग के साथ परिचय दीजिए।
- भारत में भूख की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट्स द्वारा उजागर की गई चिंताओं पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।
- भारत में भूख की समस्या के समाधान के लिए किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए।
- किए गए उपायों के बावजूद भारत में भूख के बने रहने के कारणों का उल्लेख कीजिए।
- इस संदर्भ में आगे की राह सुझाइए।

उत्तर:

ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) 2021 में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर फिसल गया है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में से 94वें स्थान पर था। भारत का स्थान पाकिस्तान (92), बांग्लादेश (76) और नेपाल (76) से पीछे है। इसके अतिरिक्त, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की 'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट', 2020 के अनुसार, भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित हैं।

भारत में भूख की स्थिति पर हालिया रिपोर्ट्स द्वारा उजागर की गई चिंताएं इस प्रकार हैं:

- बच्चों में **वेस्टिंग (Wasting)** की समस्या (लंबाई के अनुसार वजन कम होना) वर्ष 1998 और वर्ष 2002 के बीच 17.1% से बढ़कर वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच 17.3% हो गई।
- **टकराव, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 (3Cs)** ने हालिया वर्षों में भूख के विरुद्ध की गई किसी भी प्रगति को समाप्त करने की आशंका उत्पन्न की है।
- **5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर** जैसे संकेतकों में सुधार प्रदर्शित होने के बावजूद, अपर्याप्त भोजन के कारण बच्चों में अभी भी **नाटेपन (Stunting)** और **अल्पपोषण** की समस्या व्याप्त है।
- विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुपोषण अन्य ब्रिक्स सदस्य देशों की तुलना में दो से सात गुना अधिक है।

भूख और भुखमरी के संकट को रोकने के लिए किए गए कुछ नीतिगत हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

- **पोषण अभियान** को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह एक बहु-मंत्रालयी संमिलन मिशन है, जिसका उद्देश्य एक सहक्रियात्मक और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाकर जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।
- आंगनवाड़ियों के साथ-साथ **प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना** ने बच्चों (और गर्भवती तथा साथ ही स्तनपान कराने वाली महिलाओं) के लिए निःशुल्क भोजन के माध्यम से कुपोषण को कम करने के प्रयासों का निरीक्षण करने और इसका अनुपूरक बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना**, 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हेतु सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है।

विभिन्न उपायों के बावजूद भारत में भूख के बने रहने के निम्नलिखित कारण हैं:

- **नीति अपर्याप्तता के कारण:**
 - **योजनाओं का अशक्त कार्यान्वयन:** यह विभिन्न कारकों जैसे अधोगामी (टॉप-डाउन) दृष्टिकोण, खराब कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, प्रभावी निगरानी का अभाव, एकाकी दृष्टिकोण, योग्य मानव संसाधनों की कमी आदि का प्रत्यक्ष परिणाम है।
 - **सामाजिक संरचना:** कई योजनाएं आबादी के बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाती हैं, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाली जनजातियों और दलितों तक, जो स्वयं को वितरण प्रणाली से बहिष्कृत पाते हैं।
- **अन्य कारण:**
 - **खाद्य अपव्यय:** अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं एवं कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण भारत में इसके कुल वार्षिक खाद्य उत्पादन का लगभग 7% और फलों एवं सब्जियों का लगभग 30% बर्बाद हो जाता है।